आपका प्रश्न जो आपने मुझे याद दिलाया उस दिशा में भी सोच की आवश्यकता है और यह सोची जाएगी ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Next Question No. 442.

*(The question (Shri Misa R. Ganesan was absent. For answer, vide col.... infra).

*(The question (Dr. Sanjaya Sinh) was absent. For answer, vide col.... infra).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 444. Shri Maheshwar Singh.

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों का चयन

*444. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल-कूद संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय खेल प्राधिकरण विभिन्न राज्यों में कुछ विद्यालयों का चयन करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस प्रयोजनार्थ चुने गये विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है और ऐसी सुविधाएं कितने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं ; और

(ग) उन्हें दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कु. ममता बनर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 56 स्कूलों को अपनाया गया है । इस योजना में राज्यवार छात्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिये)** ।

(ग) यह योजना 1985 में शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य 8–12 वर्ष के आयु समूह में स्कूली छात्रों में प्रतिभा की खोज करना था । इस योजना में एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केट बाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबाल तथा कुश्ती खेल-विधाएं शामिल हैं योजना में छोटी आयु में खेल उत्कृष्टता के साथ छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की परिकल्पना है । इसका सम्पूर्ण खर्च भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है ।

विवरण

अंगीकृत विद्यालयों में बच्चों की संख्या (राज्य-वार)–31.3.92 तक की स्थिति

राज्य का नाम	विद्यालय का नाम	बच्चों की संख्या	
		लड़के	लड़कियां
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1. वैसली बाल उच्च विद्यालय तथा महाविद्यालय, सिकंदराबाद	17	—
	2. वी. पी. सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा	25	14
	3. लेयोला उच्च विद्यालय, वेनुकोण्डा	09	03

1	2	3	4
असम	4. सैनिक विद्यालय, गोलपाड़ा	12	—
	5. राजकीय बी. एच. एस. विद्यालय, गोलाघाट	19	15
	6. डोन बोस्को स्कूल, गोहाटी	17	—
बिहार	7. सेंट इग्नेशियस हाई स्कूल, बिहार	38	—
	8. राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, रांची	—	44
चण्डीगढ़	9. शिवालिक पब्लिक स्कूल, चण्डीगढ़	56	04
दिल्ली	10. एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, नई दिल्ली	—	14
	11. आर्मी पब्लिक स्कूल, धौला कुआं, नई दिल्ली	29	—
	12. मदर्स इण्टरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली	—	10
गोवा	13. सेंट एन्थनी हाई स्कूल, गोवा	09	—
गुजरात	14. चारुतर विद्या मण्डल, बल्लभ विद्यानगर, गुजरात	12	15
हिमाचल प्रदेश	15. राजकीय उच्च विद्यालय, माजरा	—	—
हरियाणा	16. मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय, राई	23	22
	17. सी. आर. जेड़ सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, सोनीपत	44	—
जम्मू और कश्मीर	18. टिंडले बिस्को स्कूल, शेखबाग	06	—
	19. मालिंसन बालिका विद्यालय, शेखबाग	—	01
कर्नाटक	20. सेंट जोसफस इण्डियन हाई स्कूल, बंगलौर	24	—
	21. माउण्टेन व्यू हाई स्कूल, चिकमंगलूर	10	14
	22. श्रीराम कृष्ण विद्याशाला, मैसूर	03	—
केरल	23. जी. वी. राजा खेल विद्यालय, केरल	12	20
मेघालय	24. सेंट एण्टनी हाई स्कूल, शिलौंग	27	
महाराष्ट्र	25. प्रवारा पब्लिक स्कूल, प्रवारा नगर	31	01
	26. भोंसला मिलिटरी स्कूल रामभूमि, नासिक	17	—
	27. संजीवन विद्यालय, पंचगणी जिला सतारा	14	16
	28. मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल, पुणे	18	11

1	2	3	4
मणीपुर	29. सैनिक स्कूल, इम्फाल . .	21	21
मध्यप्रदेश	30. राजकीय बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर . .	13	—
	31. महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय बहु-उद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर . . .	—	12
	32. जवाहरलाल नेहरू स्कूल, "भैल", भोपाल . . .	07	—
मिजोरम	33. राजकीय उच्च विद्यालय, मैकडोनाल्ड हिल, मिजोरम . .	—	—
नागालैण्ड	34. जोन राजकीय उच्च विद्यालय, विश्वेमा . . .	22	—
उड़ीसा	35. सेंट मैरी गर्ल्स हाई स्कूल, पुन्दरगढ़	—	06
	36. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, भुवनेश्वर	—	08
	37. बी.एस. उच्च विद्यालय, सुन्दरगढ़	38	—
पंजाब	38. राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, टाण्डा उर्मर, होशियारपुर .	09	—
	39. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, जलंधर .	—	12
	40. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, अमृतसर . .	—	—
राजस्थान	41. वनस्थली विद्यापीठ विद्यालय, वनस्थली	—	11
	42. भुपाल नोबलस माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर (राज.)	15	—
	43. श्री गुरुनानक खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीगंगानगर .	16	—
सिक्किम	44. ताशी नामग्याल अकादमी, गंगटोक	19	08
तमिलनाडु	45. मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज उच्च माध्यमिक विद्यालय, चेटपुत .	11	—
	46. श्री शारदा बालिका विद्यालय, सेलम	—	21
	47. सेंट जोसेफ माध्यमिक विद्यालय, कुड्डालोर . . .	11	—
त्रिपुरा	48. उमाकान्त अकादमी अगरतला, त्रिपुरा .	10	—
उत्तर प्रदेश	49. उदयप्रताप इण्टर महाविद्यालय, वाराणसी . . .	37	—

1	2	3	4
	50. कोलविन तालुकदार महाविद्यालय, लखनऊ	39	—
	51. एम.के.पी. इण्टर महाविद्यालय, देहरादून	—	27
प० बंगाल	52. राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, कृष्ण नगर, प० बंगाल	—	27
	53. बिधान नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय, साल्टलेक सिटी	40	—
	54. विक्टोरिया बाल विद्यालय करसिआंग दार्जिलिंग	13	—
	55. डोव हिल स्कूल, करसिआंग	—	15
	56. ताल्डो मोहनचन्द उच्च विद्यालय, ताल्डो, प० बंगाल	36	20
		829	371
	महायोग :		1200

श्री महेश्वर सिंह : उपसभापति महोदया, जहां तक मेरी जानकारी है 16 मार्च 1984 को स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया का एपेक्स बाडी के रूप में पंजीकरण किया गया था और इस उद्देश्य से किया गया था कि इस प्रकार के जो छात्र देश भर में हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए और खेल-कूद में भी प्रोत्साहन दिया जाए । 1987 तक इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में 66 स्कूलों का चयन किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि शुरू में ही ऐसे स्कूलों में भारत सरकार 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में देगी । तत्पश्चात् हर वर्ष 50 हजार रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट के लिए और निर्माण के लिए देगी । इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों का, जो उनकी पढ़ाई पर, किताबों पर और उनके भोजन पर तथा आवास पर खर्च होगा वह भी भारत सरकार वहन करेगी । खेद का विषय है कि इस योजना में उतनी सफलता नहीं मिल सकी है जितनी कि मिलनी चाहिए थी । जैसाकि मैंने कहा कि 1987 में बच्चों की संख्या 1991 दिसंबर तक 1217 थी और स्कूलों की संख्या 66 थी, अब यह घट कर 56 रह गई है और बच्चों की संख्या भी घट कर 1200 रह गई है । मैं जानना चाहूंगा कि इसके क्या कारण हैं और क्या भारत सरकार ने प्रदेश स्तर पर किसी समिति का कोई गठन किया है जो कि इस कार्यक्रम की समय-समय पर इस योजना की मोनिटरिंग करती हो या जिला स्तर या तालूका स्तर पर या रिजलल स्तर पर कोई इस प्रकार की प्रतियोगिता करवाती हो, जहां ऐसे मेधावी छात्रों का चयन किया जाता हो ?

कु. ममता बनर्जी : मैडम, मैं माननीय सदस्य की आभारी हूं जिन्होंने एक अच्छा क्वश्चन पूछा कि यह बात सच है, 1984 साल में नहीं लेकिन 1985 में एक स्कीम लांच किया था, यह एन.एस.एस. स्कीम है ।

पहले इसका थोड़ा क्राइटेरिया है, जो स्कूल में बोर्डिंग फेसेलिटी मिलती है स्टूडेंट्स को, उसी स्कूल में उसको शिक्षा के लिए, खाने के लिए, खेल-कूद के लिए पूरा इंतजाम स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया करता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जो ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया की एक

एम्पायर कमेटी है जो टाइम टू टाइम रिव्यू करती है और रिव्यू करके अगर ऐसा कोई स्कूल निकलता है जिसमें बोर्डिंग फेसिलिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है तो स्पोर्टस अथारिटी आफ इंडिया इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेक अप करती है और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि आप कोई अलग से स्कूल बताएं जिसमें होस्टल फेसेलिटीज हैं। होस्टल फेसेलिटी नहीं रहने से एक स्टूडेंट को हम लोग उधर में रखकर खेल-कूद में ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। उसको शिक्षा, उसको खेल-कूद का ट्रेनिंग और उसको स्टडी पूरी दे सकता है स्पोर्टस अथारिटी आफ इंडिया। इसी के लिए दो-चार स्कूल जो हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल है—माजरा स्कूल, जिस स्कूल में पांच लाख रुपए हमने सैंक्शन किए थे और 2.5 लाख हमने रिलीज भी किए हैं, लेकिन उस स्कूल में अभी तक कोई बोर्डिंग फेसेलिटी नहीं है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप कोई अल्टरनेटिव स्कूल दें जिसमें बोर्डिंग फेसिलटी हो तो हम लोग कर सकते हैं।

उपसभापति : सैकिंड सप्लीमेंटरी।

श्री महेश्वर सिंह : उपसभापति महोदया, मैंने यह जानना चाहा था कि क्या कोई मानिटरिंग समिति बनाई गई है जो कि समय-समय पर जिला-स्तर पर तालुका स्तर पर या रीजनल स्तर पर बच्चों की प्रतियोगिता करवाती हो?

दूसरी मेरी सप्लीमेंटरी यह है कि जैसे कि आपने स्वयं कहा कि हिमाचल प्रदेश के माजरा स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है। तो जो इस प्रकार के स्कूल हैं, उनके स्थान पर, उनको सूची से निकालकर दूसरे स्कूलों का चयन कर लिया गया है या प्रान्तीय सरकारों को यह लिखा गया है कि इसके स्थान पर वह किसी दूसरे में स्कूल का नाम आपके पास प्रपोज करके भेजें? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब से यह योजना चली है, आज तक कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी गई और कुल कितना भारत सरकार का खर्चा हुआ है?

कु० ममता बनर्जी : मैडम, माजरा स्कूल की जो बात है, मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि हम लोग 2.5 लाख रुपए रिलीज किए थे, लेकिन उनको जो बोर्डिंग फेसेलिटी देना था, वह नहीं दिया इसलिए हमारी जो एम्पायर कमेटी है स्पोर्टस अथारिटी आफ इंडिया की, यह टाइम टू टाइम रिव्यू करती है, मानिटरिंग करती है, इसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हम लोगों ने टेक-अप किया है और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप एक अलग से स्कूल दीजिए जिसमें बोर्डिंग फेसेलिटी हो so that we can start them here. और मैडम, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने कितनों को ट्रेनिंग दिया है, 1200 स्टूडेंट्स को अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं एन०एस०टी०सी० स्कीम में और आउट डोर स्कीम हमने चालू किया है। एक एस०टी०डी०सी० सेंटर चालू किया है, 22 आपरेशनल है और हम लोगों ने एक "साई" सेंटर चालू किया है और उस "साई" सेंटर में भी हमारे 700 से अधिक स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं।

श्री महेश्वर सिंह : वह फिर जबाब नहीं आया। मैंने कहा था कि कोई प्रतियोगिता होती है जिला स्तर पर?

कु० ममता बनर्जी : प्रतियोगिता तो होती है, प्रतियोगिता के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग पहले ही बोल चुके हैं मानिटरिंग समिति है। जो क्राइटेरिया है स्कूल एडाप्ट करने का, मैडम एक क्वेश्चन है "साई" का स्कूल के बारे में, "साई" का एडाप्ट करने के बारे में। जो प्रतियोगिता होती है और सम्मर टाइम में, स्कूल में जब छुट्टी रहती है, सब "साई" सेंटर्स से एक कोच उधर रहता है और उसको एक्सटेंसिव एंड इन्टेंसिव ट्रेनिंग देता है, उसको एक्सपोजर देता है और उसको तो पूरा पड़ोस में ही उसको ट्रेनिंग देता है। प्रतियोगिता तो होती है।

एक माननीय सदस्य : यह समझ में नहीं आया।

श्रीमती सत्या बहिन : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जो विद्यालयों का

खेल-कूद के प्रोत्साहन के लिए चयन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है ? क्योंकि जो लिस्ट दी गई है और उसमें जो नाम दिए गए हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश से जो मैं समझती हूं कि सबसे बड़ा प्रदेश है देशभर में, उसमें से कुल 3 विद्यालय चुने गए हैं जबकि अन्य प्रदेशों से 9–9 विद्यालय चुने गए हैं । तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या प्रक्रिया है, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

कु० ममता बनर्जी : मैडम, मैंने रिप्लाई में पहले ही कहा है कि 56 स्कूलों को एडाप्ट किया है "साई" ने एन०एस०टी०सी० में स्कीम है । हर स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन देता है, फैसेलिटी अवेलेबल हैं, उसमें हम करना चाहते हैं । यही इसका क्राइटेरिया है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्शन कमेटी भी हमारी है, वह सेलेक्शन कमेटी जो स्कूल विजिट करती है उसको साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग में हम लेते हैं और जो-जो क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग में चुना जाता है ।

श्रीमती सत्या बहिन : रूरल स्कूल नहीं चुना है ?

कु० ममता बनर्जी : नहीं, रूरल स्कूल भी हैं ।

श्री अजीत जोगी : महोदया, साई द्वारा जो शालाओं को गोद लेने की योजना है, उस योजना का सही परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बर्सिलोना ओलम्पिक में भारत का जो योगदान रहा है, यह उससे परिलक्षित होता है कि सात वर्षों में हम शालाओं को, स्कूलों को गोद में लेकर ऐसे खिलाड़ी तैयार नहीं कर सके जो हमारे लिए किसी भी तरह का पदक जीत सकें । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इस पूरी योजना में कुछ बुनियादी मौलिक परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रहा है ? मेरी दृष्टि में हमें एक जो सबसे बड़ी कमी और बुनियादी खामी है, वह यह है कि हम ऐसे बच्चों को जिनमें प्रतिभा है वह किसी शाला विशेष में प्रवेश लें, ऐसा मजबूर करते हैं । उसकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, स्थितिजन्य उसकी मजबूरियां ऐसी हो सकती हैं कि जिस शाला को आपने गोद में लिया है उसमें न पढ़ सके । तो क्या विशेषकर ऐसे कुश्ती के क्षेत्र में बहुत से ऐसे अखाड़े हैं, एक पहलवान–पप्पू यादव जो काफी अच्छा लड़ा मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं उसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा हूं । वह एक ऐसे अखाड़े में रहकर प्रशिक्षण ले रहा है जहां उसको किसी तरह की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं । उस अखाड़े से चार-पांच ऐसे प्रतिभावान बच्चे तैयार किए हैं और वह शाला चला रहे हैं । वह चाहते हैं कि जो सहायता आप इन स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी बच्चों को जहां वह पढ़ रहे हैं, वहीं सुविधा दी जाए, न कि इन गोद में ली गई शालाओं में दी जाए । क्या ऐसा कोई बुनियादी परिवर्तन आप अपनी इस योजना में करेंगे ?

एक सम्मानित सदस्य : पार्लियामेंट में अखाड़ा अच्छा है वैसे ।

कु० ममता बनर्जी : एन० एस० टी० सी० स्कीम के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को कुछ लोग ट्रेनिंग देते है । 1986 में यह स्कीम शुरू हुई है । आज 1992 में इस स्कीम को 6 वर्ष हो गए हैं । जो बच्चे इस ट्रेनिंग के अन्तर्गत हैं, मैडम, आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें जो 1200 बच्चे हैं । नेशनल लेबिल से 666 मैडल हमारे बच्चों ने जीता है और इंटरनेशनल कम्पटीशन में 14 मेडल मिले हैं । लेकिन अब इसका... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : बर्सिलोना में तो कुछ नहीं हुआ ?

कु० ममता बनर्जी : वह डिफेंट क्वेश्चन है... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : केवल भारत के स्तर पर कुछ करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए ।

कु० ममता बनर्जी : मैं आपके क्वेश्चन का पूरा रिप्लाई दूंगी। मैडम्, यह हमने आठ वर्ष से शुरू किया है। 1986 में आठ वर्ष की उम्र में जिसको भर्ती किया गया था उसकी अब ऐज 14 वर्ष है। उनका इससे जो अचीवमेंट हुआ है, उनको 666 मेडल नेशनल लेबिल पर मिले हैं और 14 मेडल इंटरनेशनल लेबिल पर मिले हैं। बर्सिलोना जाने के लिए यह बच्चे अभी ट्रेंड नहीं हैं। बर्सिलोना में जो चीज हुई है, मैडम्, उस पर कॉलिंग अटेंशन भी राज्य सभा में एक्सेप्ट हुआ है। 11 तारीख में हम लोग उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैडम, अभी हम लोग जूनियर्स को ज्यादा एक्सपोजर देना चाहते हैं। जूनियर्स को एक्सपोजर देने के लिए हमने "कैच दैम यंग प्रोग्राम" स्टार्ट किया है। अब सीनियर्स को एक्सपोजर देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम जूनियर्स को ठीक से देगा तो वह ठीक हो जाएंगे। इसीलिए हमने ग्रास रूट से शुरू किया है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ... **(व्यवधान)** खेल-कूद के लिए तो आपको जूनियर्स को एक्सपोजर तो देना ही है।

श्री प्रमोद महाजन : जूनियर्स को एक्सपोजर दे रहे हैं और सीनियर्स पागल हैं। ... **(व्यवधान)** मैं कह रहा हूं मिनिस्ट्री भी वही कर रही है ... **(व्यवधान)**

कु० ममता बनर्जी : मैडम्, जूनियर्स को हम लोग एक्सपोजर दे रहे हैं और मैडम्, आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग पंचायत लेबिल से नेशनल लेबिल तक एक पंचायत लेबिल टीम भी चालू कर रहे हैं। पंचायत लेबिल टीम ब्लौक-टू-ब्लौक चले और डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर आए और डिस्ट्रिक्ट लेबिल से स्टेट लेबिल पर आए और नेशनल लेबिल पर आए। तो हम लोग ग्रास रूट में जो राईट टू प्ले—खेल-कूद का अधिकार, सबको देने के लिए हम कर रहे हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have 30 questions on t his, and we also have a calling attention motion.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Madam Deputy Chairman, this question has come on the heels of our dismla performance in the near-complete Barcelona Olympics. I think there is nothing very unusual in what happened in Barcelona with our team because that had been our performance in all the preceding Olympics, these successive Olympics, I think. The point is that we are far behind the international standards in games and sports and steps have to be taken to overcome these short-comings. The question relates to an area on which depends the future of the country. That is, training to the school children, the young boys, by the Sports Authority of India. I would like to mkea a request to the Minister whose enthusiasm in whatever comes her way is well known. (*Interruption*). Perhaps, the CPM will also concur with me. You need not worry about it. The question is, does hse consider the programme for training of school children adequate? That is, training 1200 students all over India. They might have won 361 medals. But in a country of 890 million people, is training 1200 students an adequate programme? The second point is,....

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you are brief, some other people can be accommodation.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: My second question is, why is the boarding house criterion insisted upon? Thirdly, is the overall grant to sports and games, that is Rs. 40 crores, enough to cover the entire ground or is it an apology?

KUM. MAMTA BANERJEE: Madam, I am grateful to the senior Member of this House. Though sports is a State subject, it is a fact that our funds are very limited and we are spending only Rs. 40 crores on this. And, this time, it is reduced to Rs. 12 crores. It is most unfortunate. In European counries, they are spending ten per cent of their Budget on sports. Even in Malaysia, they are spending

more than Rs. 1000 crores on sports. But our country is spezndng only Rs. 40 crores on sports. It is very difficult to create infrastructure. That is why we have involved the public sector and the private sector also to come forward and give some resource to sports so that we can build up our sports units. Madam, I request, through you, the hon. Members of this House to fight over this matter with the Planning Commission and the Finance Ministry. (*Interruptions*)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: ...The Minister is right. We must recognise our dismal performance in Olympics. We m ust recognise the fact. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order please. Order. Order in the House please. (Interruptions).

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: ...You should take up the challenge.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do not be that enthusiastic in this House Question No. 445.

Popularisation of lab to land programmes

*445. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) in what manner 104 collaborating centres under the supervision of Eight Zonal Committes take the technology packages from the scientists to the farmers; and

(b) what effective and viable steps are taken to popularise lab-to-land programmes so that farmers could step up their production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) The technology packages are transferred by the scientists under the Lab to Land Programme at 104 Lab to land centres located in ICAR Institutes, State Agricultural Universities, Krishi Vigyan Kendras and selected Voluntary Organizations, through demonstrations, training and farm advisory services to small and marginal farmers and landless agricultural labourers. Eight zonal coordinating units of the Council supervise and monitor the Lab to Land programme in their respective zones.

(b) Under the Lab to Land Programme, small and marginal farmers and landless agricultural labourers are adopted by the lab to land centres. The survey is conducted to find out the resource endowment of the adopted farmers. The suitable low cost technologies are identified and demonstrated to the farmers for stepping up their production.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Madam, agricultural production is to be increased and productivity is to be improved. For that, the Lab to Land Programme is very much essential. Not only that. The Lab to Land Programme should be effective. I want to know whether there are enough infrastructural schemes to disseminate all the findings to the agriculturists. In this connection. I would be very glad if the Minister throws some light on the object of the project. At the same time, I also want to know from him as to how many centres are there in Tamil Nadu to disseminate such information.

SHRI K. C. LENKA: Madam, the Lab to Land centre deals with the poor farmers in the villages and demonstrates to them the low cost technologies. The main purpose of this Programme is to bring the farmers and the scientists in close contact and to introduce the relevant low cost technologies which would help in diversification of labour use and creating supplementary sources of income in the fields of agriculture, animal husbandry, sericulture, apiculture, and fisheries. Madam, these lab to land centres give vocational training to marginal and small farmers and landless labourers so that they can have additional income. So far as Tamil Nadu is concerned, in Tamil